alongwith Central Bureau of Investigation;

(b) if so, to what extent have the Commission and Bureau helped in preventing the corruption and nabbing the culprits;

(c) whether matters brought to the notice of the C.V.C keep on dragging for years;

(d) if so, what good is of C.V.C. and the steps taken to expedite the disposal of the cases under its consideration; and

(e) how many cases are pending with C.V.C. for investigation for over one year giving details thereof and the reasons for the abnormal delay in finalising the investigation and submitting reports thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT MARGARET ALVA): (a) No, Sir. The Central Vigilance Commission was set-up in February, 1964

(b) The advice of the C.V.C. and the investigations of the C B I have helped in checking corruption as well as in apprehending the culprits.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise in view of the answer to (c) above. Further the Commission does not investigate; it tenders advice on the information reports submitted to it.

Appointment without ACC approval

426. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many 1978 Batch IAS Officers have been appointed|designated as Joint Secretary, non-Ministerial Deputation Post;

(b) whether any case has been brought to the notice of the Ministry where appointments have been made without ACC approval|concurrence| information; and

(c) if so, what action has been taken by Ministry in such cases to maintain parity in the service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) The 1978 batch IAS officers have not become eligible for appointment as Joint Secretary to the Govt. of India. Hence, no officer belonging to this batch has been apopinted to this level.

(b) No, Sir.

(c) Does not arises.

Panel for M.D. in B.L.C. Ltd., Agra

427. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the PESB has created a panel of selected candidates for the post of Managing Director in Bharat Leather Corporation Limited, Agra;

(b) whether the PESB could select only one candidate for the post whose antecedents are doubtful and call for investigation;

(c) whether Government would intervene to ensure fair selection and to rebuild the image of PESB; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) The Public Enterprises Selection Board has, after assessing the suitability of candidates, found only one candidate suitable for the

post. They have accordingly recommended his name for the post to the concerned administrative Ministry. The existing procedure requires the administrative Ministry concerned to furnish vigilance clearance of candidates recommended by the PESB before forwarding the name/names for consideration of ACC. Vigilance aspects are looked into by the PESB, during the process of selection, only to the extent specifically brought to its notice.

(c) and (d) Do not arise.

संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार

428. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार के कितने मामले लाए गए हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में किस प्रकार के आरोप थे और दोषी व्यक्तियों को क्या-क्या सजा दी गई; और

(ग) भ्रष्टाचार से प्रभावित लोगों को क्या-क्या रियायतें दी गईं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मारग्रेट आल्वा : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों में, संघ लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित एक मामले में जो कि आयकर/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इत्यादि, निरीक्षक परीक्षा 1988 के प्रश्न पत्र के लीक होने में कर्मचारी चयन आयोग के तीन कर्मचारियों की तथाकथित भागीदारी संबंधित थी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई और उसने इन तीन कर्मचारियों के विरुद्ध केवल विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की

शेष दो मामलों में कर्मचारी चयन, आयोग के समूह "घ" के दो कर्मचारी आयोग की परीक्षा में छद्म रूप से बैठाने में सहायता संबंधी कार्यवाही की कोशिश करने में लिप्त पाए गए। उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

गुजरात में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

429. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के भरूच, सूरत, बड़ोदरा और पंचमहल जिलों को लक्ष्यानुसार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त जिलों के कितने गांवों को लाभ मिला है/लाभ मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री उत्तम भाई पटेल : (क) केन्द्रीय और राज्य बजट में उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुसार लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते है। जिलावार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा तय किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा इनकी निगरानी रखी जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा ही इन्हें रखा जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियों के आंकड़े रखती है